

श्रमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3---उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 52]

नई विल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 1976/माघ 7, 1897

No. 52]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 1976 /MAGHA 7, 1897

इस भाग में भित्र पुष्ठ तंस्या दो जातो है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th January 1976

S.O. 67(E)/18FB/IDRA/76.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) S.O. 72(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th January, 1974, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Devclopment and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Hind Cycles Limited, Hombay (Bombay Unit), or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period:

And, whereas the Central Government in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) by Order No. S.O. 54(E)/18FB/IDRA/75, dated the 28th January, 1975, extended the duration of the said Order upto the 28th January, 1976;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 28th January, 1977.

[No. F.2(16)/73-CUC] D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय (श्रौद्योगिक विकास विभाग)

श्चादेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1976

का० मा० 67 (म्र)/18 एक० बी० मार्ड० मार० ए०/76.—भारत संस्कार के भूत्वूर्व मौद्योगिक विकास मंत्रालय (भौद्योगिक विकास विभाग) के म्रादेश का० मा० 72 (म्र)/18 च ख / उ० वि० वि० म० /74 तारीख 29 जनवरी, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त म्रादेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास मौर विनियमन) म्राद्यित्वयम, 1951 (1051 का 65) की भ्रारा 19 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि राजपल में उक्त म्रादेश के प्रकाशन के श्रव्यवहित पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पल, करार, परिनिर्धारण, पंवाद, स्थायी म्रादेश या भ्रत्य लिखत (उनसे भिन्न जो बैंकों या वित्तीय संरथायों के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं), जिनका मेससं हिन्द साइकिल लिमिटेड, मुम्बई, (मुम्बई एकक) नामक म्रोद्योगिक उपक्रम या ऐसे म्रोद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पर्न एक पक्षकार है या जो उक्त म्रोद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, का प्रवर्तन एक वर्ष की म्रविध तक निलिंख रहेगा भौर उक्त तारीख के पूर्व उसके म्रधीन प्रोद्यूत या उद्भूत सभी म्राधकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं भौर दायत्व उक्त म्रवधि तक निलिंख तार्थेत स्थाताएं भौर दायत्व उक्त म्रवधि तक निलिंख तार्थेत स्थाताएं भौर दायत्व उक्त म्रवधि तक निलिंख निलिंख रहेगे,

श्रीर भारत सरकार, ज्योग श्रीन नागिक पूर्ति मंद्रालथ (श्रौद्योगिक विकास विभाग) ने श्रादेश संव काव श्राव 54 (ग्र) /18 च ख / उव विव विव ग्रव/75 तारीख 29 जनघरी, 1975 द्वारा उक्त श्रादेश की श्रवधि 28 जनवरी, 1976 तक बढ़ा दिया है,

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त श्रादेण को अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

श्रतः श्रव उद्योग (विकास अंशि विनियमन) श्रिधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 न ख को उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते इए. केन्द्रीय सरकार उक्त श्रादेश की अविधि 28 जनवरी, 1977 तक बढ़ाती है।

[सं० फा० 2 (16)/73 सी० यू० सी०] डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिय।